मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति ने 'एविडेंस बेस्ड वोल्यूम ऑन रूरल इन्फ्रास्ट्रकचर एंड विकसित भारत विज़न'का विमोचन किया

नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने 'विकसित भारत में ग्रामीण बुनियादी ढांचा और सामाजिक-आर्थिक विकास – पूर्वोत्तर भारत के परिप्रेक्ष्य' नामक एक नई विद्वतापूर्ण पुस्तक के लॉन्च की घोषणा की है, जिसे जामिया के वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन विभाग के प्रो. देबर्षि मुखर्जी और त्रिपुरा विश्वविद्यालय के डॉ. राजेश चटर्जी ने लिखा है। माननीय कुलपति प्रो. मज़हर आसिफ़ ने आधिकारिक तौर पर पुस्तक का विमोचन किया और इसकी प्रस्तावना भी लिखी है, जो भारत के विकास विमर्श में इसके महत्व पर प्रकाश डालती है।

जनगणना 2011 और NSSO 66वें दौर के डेटा पर आधारित पिछले अध्ययनों की सीमाओं को पार करते हुए, यह शोध एक अग्रणी, साक्ष्य-आधारित विश्लेषण प्रदान करता है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचा पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। लेखकों ने मौजूदा साहित्य में एक महत्वपूर्ण कमी की पहचान की है और चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है। सबसे पहले, वे व्यवस्थित रूप से ग्रामीण बुनियादी ढांचे का पता लगाते हैं, जो मैक्रो-स्तरीय विवरणों से परे है। दूसरे, वे इस बात पर जोर देते हैं कि बुनियादी ढांचा न केवल भौतिक है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक भी है - जिसमें जीवन स्तर में सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, पोषण और ग्रामीण सेवाएं शामिल हैं। तीसरे, यह अध्ययन अपने निष्कर्षों को विकसित हो रही सरकारी नीतियों और बुनियादी ढांचे के वितरण के संदर्भ में रखता है, जो क्षेत्रीय योजना के लिए प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चौथे, यह फील्ड साक्षात्कार, सांख्यिकीय विश्लेषण और क्षेत्रीय तुलनाओं को एकीकृत करके नवीन कार्यप्रणाली का उपयोग करता है, जो भविष्य के शोध के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।

यह पुस्तक महत्वपूर्ण जमीनी वास्तविकताओं को दर्ज करती है, जैसे कि खराब शैक्षिक स्तर ग्रामीण समुदायों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने से कैसे रोकते हैं - भले ही योजनाएं और ऋण उपलब्ध हों - क्योंकि सुनिश्चित बाय-बैक तंत्र और संस्थागत समर्थन की कमी है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि सबसे कम विकसित पंचायतों (LDPs) में, कमजोर बुनियादी ढांचा और खराब परिवहन, खासकर सूर्यास्त के बाद, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अलगाव का कारण बनता है, जिससे निवासी बैंकिंग और प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्थानीय सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। ये अंतर्दृष्टि नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों और वित्तीय संस्थानों के लिए क्षेत्र के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप डिजाइन करने के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन के रूप में काम करती हैं।

लॉन्च के दौरान, प्रो. मज़हर आसिफ ने लेखकों को उनके अग्रणी योगदान के लिए सराहा और भारत की विकसित भारत पहल के लिए पूर्वोत्तर भारत में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह किताब संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास, समानता और सामाजिक न्याय पर फिर से सोचने के लिए एक मजबूत विश्लेषणात्मक ढांचा और कार्रवाई योग्य साक्ष्य पेश करती है।

यह किताब, 'रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सोशिओ इकोनोमिक ग्रोथ इन विकसित भारत-पर्सपेक्टिव ऑफ़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया', ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और पूर्वोत्तर भारत के अध्ययन में रुचि रखने वाले विद्वानों, नीति निर्माताओं, विकास एजेंसियों और छात्रों के लिए बहुत प्रासंगिक होगी।'

प्रोफेसर साइमा सईद
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी